व्यवसायी वर्ग ने कहा 'अबतक का सबसे बेहतरीन बजट'

कोलकाता, समाज्ञा : लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने शुक्रवार की सुबह अंतरिम बजट पेश किया। बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों व मजदूरों को राहत, करदाताओं को राहत पहुंचाकर पीएम मोदी की सरकार ने मास्टरस्ट्रोक चल दिया है। इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी। बजट पेश होने के बाद सभी लोग इस पर अपने विचार देने लगे। इसी क्रम में समाज्ञा ने भी कुछ विशेषज्ञों से बजट पर उनकी राय जाननी। खुशबू सिंह

आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन **संजीव गोयनका** ने कहा कि इस बार का अंतरिम बजट केवल एक बजट नहीं है बल्कि देश की दीर्घकालिक विकास यात्रा का साहसी नीति है। इस बजट में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। वित्त मंत्री ने किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी और कृषि जैसे क्षेत्रों को लाभान्वित किया है।

सिद्धा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर **संजय जैन** ने कहा कि कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक बजट है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायता करेगा।

बुक माई अकाउंट के प्रेसिडेंट **सुनिल कुमार धनानिया** ने बताया कि इसबार का अंतरिम बजट अबतक का सबसे बेरहतरीन बजट है। इस बजट में सभी वर्गों के खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए सरकार ने 5 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी वालों को पूर्ण टैक्स छूट दे दी है, यह बजट की सबसे खास बात रही। बजट में किसानों व मजदूरों को विशेष ध्यान दिया गया है।

शोभा टाईल्स के डायरेक्टर **कृष्णा कुमार सिंह** ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। मैं इस बजट की सराहना करता हूं। 5 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी वालों को पूर्ण टैक्स छूट दे देने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

स्पीट वेज लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर **अभय नारायण सिंह** ने कहा कि बजट मुख्य तौर पर मध्यम वर्ग के लिए था। बजट से इससे ज्यादा की उम्मीद थी। बजट में जीएसटी की दरों में कमी के लिए भी कुछ रहता तो जनता और ज्यादा लाभांवित होती।

अश्विनी लोहिया ने बताया कि इस बजट में सभी वर्गों के लोगों पर ध्यान दिया गया है। इस बजट को मैं 100 में से 80 अंक दूंगा।

सीएफ आई लॉजिस्टिक्स के एसीसी **अशोक अग्रवाल** ने कहा कि यह एक आशामुखी बजट है। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि इसमें रक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके पहले किसी भी सरकार ने रक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया था।

बीडी ग्रुप के चेयरमैन **विनय दूबे** ने कहा कि यह वाकई में एक एतिहासिक बजट है। इस बजट में मध्यम वर्ग, किसाव व मजदूर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा रक्षा पर भी विशेष महत्व दिया गया है जो कि इससे पहले किसी बजट में देखने को नहीं मिला।

इडेन रियालटी ग्रुप के चेयरमैन **सच्चिदानंद राय** ने बताया कि यह बजट एक तरीके से देखा जाय तो चुनावी बजट है लेकिन सरकार ने इसमें विकास को भी अनदेखा नहीं किया है। मजदूरों व किसानों को बजट में इतना महत्व देना एक क्रांतिकारी दिशा की ओर काम होने को दर्शा रहा है।

जगमोहन बागला ने कहा कि कुछ नया नहीं लगा बजट में। सरकार ने बजट के जरिए एक चुनावी दांव खेला है। फिर भी बजट को ओवरऑल अच्छा बजट कह सकेत हैं।

नंदराम मार्केट के व्यवसायी **मानिक चंद्र सेठिया** ने बताया कि बहुत बढिया बजट है। 5 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी वालों को जो पूर्ण टैक्स की छूट दी गयी है इससे लोगों को काफी सुविधा होगी।

पारस ग्रुप के एमडी **मनोज खण्डेलवाल** ने बताया कि औसत बजट है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जनता को लुभाने वाला बजट बनाया गया है।

सुबोध छाजर ने बताया कि ओवरऑल बजट है। 5 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी पर पूर्ण टैक्स की छूट देना एक तरह से मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए किया गया है।

ओम प्रकाश रूईया ने बताया कि बजट से मध्यमवर्ग के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा किसानों व मजदूरों को भी राहत मिलेगी।

संजय बुधिया ने कहा कि बजट बिलकुल अपेक्षित है। इसमें आगे बढ़ने के इरादे की रूपरेखा तैयार की गयी है। व्यक्तिगत कर में छूट की सीमा में वृद्धि की सबसे बड़ी घोषणा के अलावा किसानों, मत्स्य, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और ऊर्जा को राहत देने की घोषणा की गई है।

नंपा स्टील एण्ड पावर (इंडिया) के चेयरमैन **मनोज कुमार सिंह** ने केंद्रीय आम बजट को सभी के हितों का ख्याल रखने वाला बजट करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्रीन नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था और इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया है। आम लोगों को पांच लाख रुपये तक के आयकर में छूट का प्रावधान, साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को तीन हजार रुपये वार्षिक पेंशन तथा किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये दिये जाएंगे। रक्षा बजट में जिस तरह से इजाफा किया गया है, इससे देश के जवानों को बड़ी ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के गरीब और पिछड़े लोगों के साथ-साथ उद्योग के हितों का भी ध्यान रखा है। यह बजट अभूतपूर्व बजट है तथा इस बजट के माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास होगा।

जीएसटी दोस्त **विकास धनानिया** ने बताया कि बजट हर वर्ग के लोगों को सहूलियत देने वाला है। इसके अलावा मजदूर व किसान पर जिस प्रकार ध्यान दिया गया यह किसी सरकार ने पहली बार किया है। मात्र 100 रुपये मासिक जमा करने से 3 हजार का पेंशन देने का स्कीम से सरकार ने साबित किया वह 'सबका साथ सबका विकास' की राह पर चलती है।

कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष **कमल जैन** एवं प्रदेश महामंत्री **राजा राय** ने कहा की बजट में अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को सुविधाएं दी गई है लेकिन व्यापारी वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया है जबकि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में रीड की हड्डी का काम करते हैं। उन्होंने कहा की वे एक बार फिर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को नए सिरे से एक ज्ञापन भेजकर व्यापारियों के प्रमुख मुद्दों को सुलझाने का आग्रह करेंगे।

जीनियस कन्सल्टैंट्स लि. के सीएमडी **आरपी यादव** ने कहा कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के प्रस्तावों से निश्चित तौर पर देश में उल्लेखनीय बदलाव होगा। घोषित नए प्रस्ताव प्रैक्टिकल हैं तथा इनके सकारात्मक नतीजे आएंगे। पांच लाख रुपए तक की आय पर कर शून्य करने की पहल भी काफी सराहनीय है।

भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड के एमडी **बजरंग कुमार चौधरी** ने बताया कि चुनावी साल होने के चलते सरकार ने अंतिरम बजट में कृषि व सोशल सेक्टर पर जोर दिया लेकिन साथ ही सरकार ने कई लोकप्रिय प्रस्तावों की भी घोषणा की। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। इन प्रस्तावों व घोषणाओं के सामाजिक विकास पर बेहद असर पड़ेगा। साथ ही आर्थिक मांग में बढ़ोतरी आएगी।

सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह अंतरिम बजट है और इस लिहाजे से बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। सालाना 5 लाख रुपये तक कमाने वालों के लिए कर माफ की गयी है। किसानों के लिए भी बजट में जगह बनाई गयी है। समाज के हित के लिए यह बजट है जिसमें मूल सीविधाओं का ध्यान रखा गया है। खास बात है कि यह बैलेंस्ड बजट है। यह अंतरिम बजट है, पूरा बजट होता तो ज्यादा अच्छा होता।

संदीप गर्ग ने कहा कि बजट कुछ खास नहीं था। लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, मगर वैसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा से मध्यम वर्ग के लोगों को आशा थी जो वे पूरा नहीं कर पाए। व्यवसायी वर्ग को जिससे राहत मिले वैसा कुछ इस बजट में दिखाई नहीं दिया। बेहतर होता अगर उद्योग व मध्यम वर्ग को राहत मिलती और ग्राहकों को फायदा होता। बजट में ऐसी कई चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया।

बृजमोहन गाड़ोदिया ने बताया कि इस साल का बजट लुभावना बजट है। मुख्य रूप से यह बजट निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। देश की जनता इस बजट से काफी खुश होगी।

हावड़ा जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष **संजय भरतिया** ने चौमुखी विकास व सर्वजन हिताय बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए बजट की सराहना की है। संजय भरतिया ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े गणराज्य भारत में आजादी के बाद से यह पहला गौरवशाली विकासशील बजट पेश किया गया है। बजट में सभी वर्ग किसान, मजदूर व्यापारी, नौकरी पेशा विशेषकर न्यूनतम आयवर्ग व मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।

बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ **केतन सेनगुप्ता** ने बजट पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा कि इस साल के बजट में रियल एस्टेट उद्योग के लिए बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं जो नई संपत्तियों को खरीदने के लिए अधिक मांग की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर रियल एस्टेट उद्योग में इस साल के बजट में बहुत कुछ है।

सिल्वन प्लाई के **जेपी सिंह** नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्रित्व काल में इस बार जो अंतरिम बजट पेश किया गया है वह हर दृष्टि से बेहतर है। यह संतुलित बजट है। इससे समाज के हर तबके पर ध्यान दिया गया है। किसानों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खास किया है, यह जरूरी था। मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से बड़ी राहत मिली है।

सुशील पोद्दार ने कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलेगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, केंद्र का यह बेहद सराहनीय फैसला है। ट्रेडर्स के लिए डीआईपीपी का फैसला भी सराहनीय। न्होंने कहा कि ट्रेडर्स के लिए विशिष्ट नहीं था। कहा जाए तो यह मिलाजुला बजट था, बजट की खास बात यह रही कि यह बैलेंस्ड था।

हावड़ा के **कृष्णा सिंह** ने कहा कि अंतरिम बजट की 3 खास बात रही। पहली 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलेगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरी 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव व तीसरी छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम किसान) योजना की घोषणा। तीनों फैसले सराहनीय हैं और यह उज्ज्वल भारत की शुरुआत है। आगे कोई भी सरकार रहे इन तीनों विषयों को आगे बढ़ाना होगा

बासु इंटरनेशनल के डायरेक्टर **उदय साव** ने बजट की सराहना करते हुए बताया कि यह बजट काफी अच्छा बजट रहा है। यह बजट निम्न वर्ग के लोगों के लिए गोल्डेन चांस है। मुख्य रूप से 5 लाख पर टैक्स फ्री करने की वजह से लोगों में खुशी है। वहीं इस बजट से आने वाले दिनों में फायदा होगा। अगर मोदी सरकार वापस आती है तो भविष्य में और अच्छा बजट आएगा।

व्यवसायी **राजेंद्र प्रसाद साव** ने इस साल के अंतरिम बजट को एक बेहतर व संतोषजनक बजट बताया है। उनका कहना कि उक्त बजट निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग के व्यवसायियों के लिए माना जा रहा है क्योंकि उनके लिए काफी कुछ आया है। वहीं देश की हर जनता को इससे खुशी होनी चाहिए।